



सांध्य दैनिक 4PM



मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु कहते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है, अर्थात् पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत।

-कबीर दास

जिद...सच की

www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube | 4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक: 24 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, बुधवार 25 फरवरी, 2026

सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड पाकिस्तान की राह... 7 पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया... 3 शिक्षा व्यवस्था को रद्दी बना... 2

योगी के सबसे करीबी विधायक उमाशंकर पर इनकम टैक्स का छापा बलिया स्थित आवास और कार्यालय में भी छापेमारी हुई

- » उमाशंकर ईडी छापा मामले में बीजेपी में बन रही है विद्रोह की स्थिति
- » राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह खुलकर आये समाने
- » लखनऊ में उनके आवास और सोनभद्र के ठिकानों पर रेड मारी गई है

4पीएम न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। आखिर वही हुआ जिसका डर था। आज सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 50 से ज्यादा अधिकारियों ने सीएम योगी के सबसे करीबी विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर छापा मार दिया। इनकम टैक्स के इस छापे की कार्रवाई जंगल में आग की तरह फैल गयी और हर कोई छापे की कार्रवाई के टाइम को लेकर बड़े राजनीतिक एंगल को तलाशने में जुट गया।

सीएम योगी इन दिनों अपनी तीन दिवसीय विदेश यात्रा के तहत जापान में हैं और उनके करीबी विधायक के घर पर छापा पड़ गया। उमाशंकर जैसे तो बसपा के टिकट पर इस बार का विधानसभा चुनाव जीते हैं और अधिकारिक तौर पर वह पूरे यूपी में बसपा के इकलौते विधायक हैं। उमाशंकर पर पड़े छापे को राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली वर्सेज यूपी की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नींद उड़ा देने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह रेड नहीं बल्कि एक संदेश है और संदेश हमेशा शब्दों से नहीं टाइमिंग से पढ़ा जाता है। टाइमिंग यही इस कहानी का असली किरदार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जापान की धरती पर निवेश और विकास का सपना बेच रहे हैं और इधर उनके सबसे करीबी माने जाने वाले चेहरे के दरवाजे पर केंद्रीय एजेंसी की दस्तक हो जाती है। सवाल यह नहीं कि छापा क्यों पड़ा सवाल यह है कि छापा अभी क्यों पड़ा? क्या



राजनीतिक संकेत बन चुके हैं छापे

सच यह है कि इस देश में छापे अब सिर्फ जांच नहीं रहे वह राजनीतिक संकेत बन चुके हैं। वह बताते हैं कि कौन लाइन में है और कौन लाइन से बाहर जाने की हिम्मत कर रहा है। वह डर पैदा करते हैं संदेश देते हैं और कभी कभी सीमाएं भी तय कर देते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है कि छापे में क्या मिला और उससे बड़ा सवाल यह है कि इस छापे से किसे क्या संदेश मिला। क्योंकि भारत की राजनीति में छापे सिर्फ अलमारी नहीं खोलते। वह इरादे खोलते हैं, रिश्ते खोलते हैं, और कभी-कभी सत्ता की असली कहानी भी खोल देते हैं।



लखनऊ में 3 गाड़ियों से पहुंची आयकर टीम, 50 से ज्यादा अफसर खंगाल रहे हैं दस्तावेज

हर कदम शतरंज की चाल

राजनीति में संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां हर कदम शतरंज की चाल होता है। और यह चाल भी साधारण नहीं है। उमाशंकर सिंह कोई साधारण विधायक नहीं हैं। वह बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक भी हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ टैक्स चौकी की जांच है या फिर यह सत्ता के भीतर और सत्ता के ऊपर चल रही अदृश्य रस्साकशी का हिस्सा है? यह पहली बार नहीं है जब एजेंसियों की गाड़ियां राजनीतिक घरो के बाहर रुकी हों। लेकिन हर बार सरकारें यही कहती हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। और जनता हर बार यही पूछती है कि कानून को काम करने की याद सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही क्यों आती है? क्या कानून की घड़ी भी राजनीतिक कैलेंडर देखकर चलती है? क्या जांच एजेंसियों की दिशा कम्पास से नहीं बल्कि सत्ता के इशारों से तय होती है?

भ्रष्टाचार आज ही पैदा हुआ? क्या दस्तावेज आज ही अचानक धरती से निकले? या फिर यह सब पहले से फाइलों में कैद था बस सही वक्त का इंतजार हो रहा था?

जीरो से हीरो अरबों/करोड़ों का अंबार

विधायक उमाशंकर सिंह का जीरो से शुरू हुआ सफर आज करोड़ों अरबों की उंचाइयों पर है। कहते हैं कि राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं होती यह किस्मत साहस अवसर और सिस्टम को पढ़ लेने की कला का नाम है। और

अगर इस कला का कोई जीवंत उदाहरण ढूंढना हो तो नाम आता है उमाशंकर सिंह। एक ऐसा नाम जो कभी भीड़ का हिस्सा था लेकिन आज भीड़ उसके दरवाजे के बाहर खड़ी दिखाई देती है। यह कहानी किसी रजवाड़े में पैदा हुए वारिस की नहीं है। यह कहानी उस शख्स की है जिसने जमीन से शुरुआत की धूल

फांकी सिस्टम को करीब से देखा और फिर उसी सिस्टम के भीतर अपनी जगह बना ली। बलिया की गलियों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का सफर उमाशंकर ने बहुत ही करीने से पूरा किया। कंपनियां बनाई व्यापार किया और सत्ता की ताकत के बल पर अकूत दौलत को इक्टटा किया।



उत्तर प्रदेश की राजनीति की नींद उड़ा देने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह रेड नहीं बल्कि एक संदेश है और संदेश हमेशा शब्दों से नहीं टाइमिंग से पढ़ा जाता है।

सुबह-सुबह टीम ने दी दबिश

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों सुबह करीब सात बजे विधायक के आवास पर पहुंची। अधिकारियों ने पहुंचते ही परिशर को घेर लिया और अंदर-बाहर की आवाजाही सीमित कर दी। बताया जा रहा है कि टीम में लगभग 30 से अधिक अधिकारी शामिल हैं जिनके साथ स्थानीय पुलिस फोर्स भी तैनात है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग कुछ वित्तीय लेन-देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है। हालांकि विभाग की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घर के भीतर मौजूद फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। कार्रवाई कई घंटों तक चलने की संभावना जलाई जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और मोड़िया को भी दूर रखा गया है।



शिक्षा व्यवस्था को रद्दी बना रही है सरकार : अखिलेश

शिक्षा छीनकर पीडीए समाज को अंधेरे में धकेलने की साजिश, सरकारी स्कूल बंद होने का खुलासा : 'विकास नहीं, विनाश का दस्तावेज'

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को रद्दी बनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद करना देश के भविष्य के खिलाफ सुनियोजित साजिश है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले उत्तर प्रदेश में विलय के नाम पर 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई थी और अब राज्यसभा में खुद यह स्वीकार किया गया है कि पिछले पांच वर्षों में देशभर में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अखिलेश यादव ने इसे केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि जब स्कूल बंद होते हैं तो केवल इमारतें नहीं बंद होती बल्कि गरीबों के बच्चों के सपनों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं।

अखिलेश यादव ने भाजपा की नीतियों को शिक्षा-विरोधी बताते हुए कहा है कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज में जागरूकता और वैज्ञानिक सोच पैदा करती है। उनके अनुसार भाजपा की विचारधारा



इस जागरूकता से डरती है क्योंकि एक शिक्षित समाज सवाल पूछता है और सत्ता से जवाब मांगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की संकीर्ण सोच और एकरंगी विचारधारा बच्चों को स्वतंत्र सोच से दूर रखना चाहती है। यही वजह है कि किताबों

का वितरण बाधित होता है, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है और सरकारी स्कूलों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल शिक्षा का संकट नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है।

शिक्षा छीनकर अवसरों पर पहरा

सपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बंद होने का सबसे बड़ा असर पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) समाज के बच्चों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों के सहारे ही शिक्षा और पोषण दोनों प्राप्त करते हैं। मिड-डे मील जैसी योजनाएं न केवल बच्चों को स्कूल से जोड़ती हैं बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्कूल बंद होने से ये बच्चे शिक्षा और पोषण दोनों से वंचित हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक अपराध करार देते हुए कहा कि यह नीति गरीबों को स्थायी रूप से श्रमिक और मजदूर बनाए रखने की कोशिश है, ताकि वे कभी बराबरी की दौड़ में शामिल न हो सकें।

निजी स्कूलों की 'लूट' का रास्ता साफ करने की कोशिश

अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि सरकारी स्कूल बंद होने से निजी स्कूलों की मनमानी और आर्थिक शोषण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की पूरी कमाई बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, परिवहन और अन्य खर्चों में खत्म हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक तरफ खातों में पैसे डालने का दिखावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई, टैक्स और आवश्यक सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर जनता से कई गुना ज्यादा वसूल लेती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी शिक्षा खत्म हो गई तो लाखों परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो जाएंगे और इससे सामाजिक असमानता और गहरी हो जाएगी।

शिक्षकों का मनोबल टूटा शिक्षा व्यवस्था बिखरी

सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में शिक्षकों का सम्मान कम हुआ है और उन्हें पढ़ाने के बजाय गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। इससे शिक्षकों का मनोबल गिरा है और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक, अभिभावक और छात्र-तीनों के बीच विश्वास का रिश्ता कमजोर हो गया है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष है और यह असंतोष आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

महिलाओं और अभिभावकों पर भरोसा

अखिलेश यादव ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा और गरीब परिवार, खासकर महिलाएं, भाजपा को सत्ता से बाहर करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि हर मां अपने बच्चे को शिक्षित देखना चाहती है और जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो यह सपना टूट जाएगा। उन्होंने 'पीडीए पाठशाला' आंदोलन को तेज करने का संकेत देते हुए कहा कि शिक्षा बचाने की लड़ाई अब सामाजिक आंदोलन का रूप लेगी।

नकलविहीन परीक्षाओं का सरकारी दावा खोखला

एसटीएफ के छापे में बेनकाब हुआ 'सॉल्वर सिंडिकेट', 5 हजार में बिक रही थी ईमानदारी

यूपी बोर्ड परीक्षाओं में सामूहिक नकल के बड़े गैंग का पर्दाफाश

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ/मैनपुरी। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को नकल-विहीन और पारदर्शी बनाने के सरकारी दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इन्हीं परीक्षाओं के बीच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक ऐसे संगठित नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था की साख को झकझोर कर रख दिया है।

मैनपुरी जिले के महाराज सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में एसटीएफ की छापेमारी में कॉलेज प्रबंधन, शिक्षक और सॉल्वर समेत छह आरोपियों की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि नकल केवल छात्रों की गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित 'टेका उद्योग' बन चुकी है।

गिरफ्तार आरोपियों में कॉलेज प्रबंधन से जुड़े आशीष, शिक्षक अरुण कुमार उर्फ टिकू, शिक्षक अनूप कुमार, और सॉल्वर शिव चौहान, अवनीत तथा अभिजीत सिंह शामिल हैं। जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क कॉलेज के प्रधानाचार्य अमरीश और उसके करीबी लोगों की मिलीभगत से संचालित हो रहा था।

टेके पर पास कराने का नेटवर्क, शिक्षा का 'काला बाजार'

एसटीएफ की जांच ने जिस सच्चाई को उजागर किया है, वह चौकाने वाली है। कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा को ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि 'टेका व्यवस्था' में बदल दिया था। परीक्षार्थियों से मोटी रकम लेकर उनकी उत्तर पुस्तिकाएं सॉल्वरों से लिखवाई जा रही थी। इसके अलावा, कई मामलों में शिक्षक खुद उत्तर बोल-बोलकर छात्रों से लिखावत रहे थे। यह केवल व्यक्तिगत स्तर की नकल नहीं थी, बल्कि एक संगठित आपराधिक नेटवर्क था, जिसमें प्रबंधन, शिक्षक और बाहरी सॉल्वर सभी शामिल थे। परीक्षा केंद्र को ही नकल का 'सेफ जॉन' बना दिया गया था, जहां नियमों का पालन केवल कागजों में हो रहा था, हकीकत में नहीं।

5 हजार रुपये में बिक रही थी मेहनत और भविष्य

एसटीएफ के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क का आर्थिक मॉडल बेहद व्यवस्थित था। प्रति परीक्षार्थी प्रति पेपर लगभग 5 हजार रुपये वसूल जा रहे थे। यानी एक छात्र को एक विषय में पास कराने के लिए हजारों रुपये का सौदा हो रहा था। सॉल्वरों को भी इस काम के लिए अलग से भुगतान किया जा रहा था। यह रकम इस बात का प्रमाण है कि नकल अब मजबूती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित 'व्यवसाय' बन चुकी है, जिसमें शिक्षा को मुनाफे के साधन में बदल दिया गया है। छापेमारी के दौरान एसटीएफ को मौके से दो लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं, इंटरमीडिएट गणित की पुस्तक, जीव विज्ञान का प्रश्नपत्र, छह मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। ये सभी साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि परीक्षा केंद्र को ही नकल का अड्डा बना दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में नकल और परीक्षा माफिया का इतिहास पुराना रहा है। सरकारें बदलती रहीं, दावे होते रहे, लेकिन समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। परीक्षा माफिया केवल छात्रों को पास कराने का काम नहीं करता, बल्कि यह पूरी शिक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इससे अयोग्य छात्र आगे बढ़ते हैं और योग्य छात्र पीछे छूट जाते हैं। इसका असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भविष्य में प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।

परीक्षा माफिया की जड़ें कितनी गहरी?

सरकारी दावे बनाम जमीनी सच्चाई

प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग लगातार यह दावा करते रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह नकल-विहीन और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, उड़नदस्ते और सख्त निगरानी की बात कही जाती रही है। लेकिन मैनपुरी की यह घटना इन दावों की पोल खोलती है। सवाल यह है कि जब परीक्षा केंद्र पर ही प्रबंधन और शिक्षक इस नेटवर्क का हिस्सा थे, तो निगरानी व्यवस्था किसके भरोसे थी? क्या निगरानी केवल औपचारिकता बनकर रह गई है? एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक कॉलेज या एक गिरोह तक सीमित मामला नहीं हो सकता। जांच में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संभावित केंद्रों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। यह संभावना जताई जा रही है कि इस तरह के गिरोह अन्य जिलों में भी सक्रिय हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं भारत की सांस : डॉ. शेखर पाठक

सपा दफ्तर में आयोजित चर्चा गोष्ठी में दहाड़ें डा. शेखर पाठक

पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने आयोजित की थी गोष्ठी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

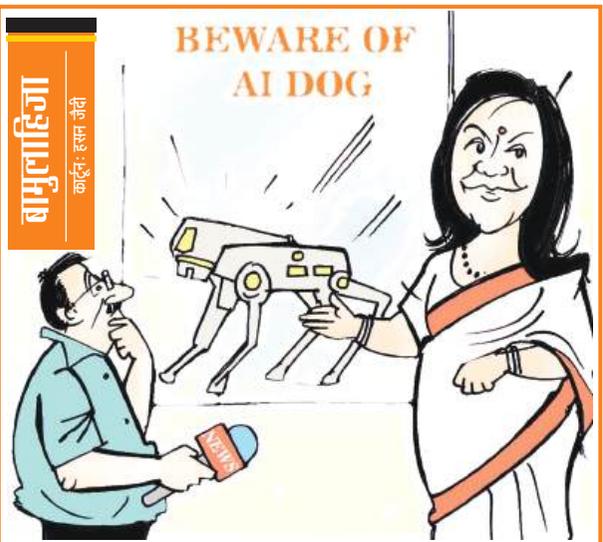
लखनऊ। हिमालय को लेकर अक्सर देश की राजनीति और विकास की बहसों में भावनात्मक बातें होती हैं, लेकिन जाने-माने पर्यावरणविद् और इतिहासकार डॉ. शेखर पाठक ने साफ शब्दों में कहा कि हिमालय कोई कविता या पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा की जीवंत दीवार है। उनके अनुसार हिमालय में हो रहे पर्यावरणीय असंतुलन का प्रभाव केवल उत्तराखंड या हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे भारत के मानसून, जल संसाधनों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और अवैज्ञानिक निर्माण कार्य आने वाले समय में बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। चारधाम यात्रा मार्ग के निर्माण और अन्य परियोजनाओं के दौरान पर्यावरणीय संतुलन को अनदेखी ने पहले ही केदारनाथ जैसे क्षेत्रों में भीषण भूस्खलन और बाढ़ की स्थितियां पैदा की हैं। उनका



मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन बिना पर्यावरणीय संतुलन के विकास आत्मघाती साबित हो सकता है।

डॉ. पाठक ने यह भी चेतावनी दी कि हिमालय केवल पर्यावरण का ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। तिब्बत, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भू-राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिससे हिमालय का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया के 'हिमालय बचाओ आंदोलन' का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी समाजवादियों ने हिमालय की सुरक्षा को राष्ट्रीय अस्तित्व से जोड़ा था। डॉ. पाठक ने स्थानीय समुदायों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जनभागीदारी आवश्यक है।



चुनाव आयोग की मनमानी रोकने को न्यायिक निगरानी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश में न्यायिक अधिकारियों की कहीं गयी है बात

विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल

4पीएम न्यूज नेटवर्क

कोलकता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बवाल जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की निगरानी में एसआईआर कराए जाने का आदेश दिया।

टीएमसी नेता डॉ. शशि पांजा ने को



सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। टीएमसी नेता डॉ. शशि पांजा ने कहा है कि से बात करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट की पूरी नजर है। पश्चिम बंगाल की मतदाता

सूची में एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है वह सही तरीके से नहीं हो रही है। यही कारण है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि न्यायिक अधिकारी एसआईआर की देख-रेख करेंगे।

एसआईआर का जो वेरिफिकेशन है उसमें बहुत सारे मतदाताओं को संदेह में रख दिया गया है कि वे देश के नागरिक हैं या नहीं? इस देश के मतदाता हैं या नहीं? यह चुनाव आयोग की चाल

है। शशि पांजा ने कहा आयोग इस पर नियंत्रण करके अपनी शक्ति का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा है। आयोग की इस मनमानी को रोकने के लिए उनके ऊपर न्यायिक अधिकारी रखे गए हैं। जब इसका मूल्यांकन किया गया कि 250 न्यायिक अधिकारी और बहुत सारे वेरिफिकेशन करने हैं तो पाया गया कि इतने सारे न्यायिक अधिकारी भी समय से यह काम समाप्त नहीं कर पाएंगे। इस कारण यह मुझाव दिया गया है कि झारखंड और ओडिशा के हाईकोर्ट से जो रिटायर्ड अधिकारी हैं आयोग उनके द्वारा इस कार्य को समाप्त करने की कोशिश करें।

सूची तैयार, सरपेंस बरकरार, बंगाल में चुनावी खेल का नया अध्याय

» एसआईआर ने बदले हालात क्या ममता बनर्जी ने पलट दी चुनावी बाजी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सन्नाटा जितना गहरा है उसके भीतर छिपा विस्फोट उतना ही खतरनाक माना जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की घड़ी नजदीक है।

एसआईआर बंगाल में महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही बल्कि यह वह दस्तावेज बन गया जो तय करेगा कि आने वाले चुनाव में किसकी जमीन खिसकेगी और किसकी सत्ता की जड़ें और मजबूत होंगी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को सिर्फ कागजी कवायद नहीं रहने दिया बल्कि इसे लोकतंत्र और अस्तित्व की लड़ाई में बदल दिया। सड़कों से लेकर अदालत तक बूथ से लेकर जनता तक हर मोर्चे पर उन्होंने एक योद्धा की तरह मोर्चा संभाला।



एक तूफान गुजर चुका है दूसरा तूफान आने वाला है?

बंगाल की राजनीति में एक तूफान गुजर चुका है लेकिन असली भूकंप अभी बाकी है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि यह पूरी कवायद लोकतंत्र की मजबूती के लिए थी या सत्ता के खेल की एक सुनियोजित पटकथा और उसी के साथ तय होगा कि बंगाल की अगली सुबह किसके नाम लिखी जाएगी।

एसआईआर के बाद किसका पलड़ा भारी

एसआईआर की प्रक्रिया ने बंगाल के हर जिले में बेचैनी पैदा कर दी। हजारों नामों के सत्यापन संशोधन और संभावित विलोपन की खबरों ने आम मतदाताओं को असमंजस

में डाल दिया। लेकिन इस पूरे दौर में सबसे बड़ा अंतर यह रहा कि जहां बीजेपी इस प्रक्रिया को फर्जी वोटों की सफाई बताकर अपनी जीत का रास्ता साफ करने की

रणनीति बना रही थी वहीं ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देकर जनता के बीच प्रतिरोध का माहौल खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने प्रशासनिक स्तर से लेकर

राजनीतिक मंच तक हर मोर्चे पर सक्रियता दिखाई। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया हर नाम की निगरानी की गई और यह सुनिश्चित करने की

कोशिश हुई कि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से बाहर न हो। इसका सीधा संदेश गया ममता लड़ रही हैं और खुलकर लड़ रही हैं।

लड़ाई अभी जारी है लेकिन बढ़त ममता के पास

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एसआईआर ने राजनीतिक समीकरणों को जरूर बदला है लेकिन इसने ममता बनर्जी की स्थिति को कमजोर नहीं किया। इसके उलट इस प्रक्रिया ने उनकी छवि को एक मजबूत और लड़ने वाली नेता के रूप में और सुदृढ़ किया है। आने वाले चुनावों में इसका क्या असर होगा यह भविष्य बताएगा लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल की इस सियासी लड़ाई में ममता बनर्जी पीछे नहीं बल्कि आगे खड़ी हैं।



दूसरे राज्यों की तुलना में बंगाल क्यों अलग है?

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर विवाद हुए लेकिन वहां विपक्ष इस मुद्दे को व्यापक जन आंदोलन में नहीं बदल सका। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सीधे जनता से जोड़ा। उन्होंने यह



संदेश देने में सफलता पाई कि यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि हर मतदाता के

अधिकार की है। यही कारण है कि बंगाल में एसआईआर राजनीतिक दबाव का हथियार बनने के बजाय राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। भाजपा ने बंगाल में संगठनात्मक विस्तार और चुनावी तैयारी पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन

एसआईआर के मुद्दे पर ममता की आक्रामक प्रतिक्रिया ने भाजपा की रणनीति को चुनौती दी है। ममता ने इस पूरे मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जनता से जोड़ा। इससे भाजपा के लिए यह प्रक्रिया चुनावी लाभ का सीधा जरिया नहीं बन पाई।

क्या सीटों का समीकरण बदल जाएगा?

अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सबसे बड़ा असर सीटों के माइक्रो-मैनेजमेंट पर पड़ेगा। कुछ हजार वोटों के अंतर से जीत-हार तय होने वाले दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का हर बदलाव निर्णायक साबित हो सकता है। अगर बड़ी संख्या में नाम हटते हैं तो बीजेपी इसे अपनी जीत का

आधार बनाएगी। लेकिन अगर नाम हटाने की प्रक्रिया में त्रुटियां सामने आती हैं या विरोध बढ़ता है तो यह ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति की लहर पैदा कर सकता है। यानी मतदाता सूची सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगी यह आने वाले चुनाव की दिशा तय करने वाला हथियार होगी।

सियासी चक्रवात में मथ गया पश्चिम बंगाल

एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल में जो सियासी चक्रवात उठा, उसने सिर्फ मतदाता सूची को नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक संतुलन को झकझोर दिया। आरोप लगे कि लाखों नामों पर तलवार लटक रही है सवाल उठे कि क्या यह सिर्फ शुद्धिकरण है या सियासी शिकार? क्या यह लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने की कवायद है या चुनावी गणित को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति? इन सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जीत के दावे तेज कर दिए हैं जबकि ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिया है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल जंग तो अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद शुरू होगी। अब निगाहें टिकी हैं उस अंतिम सूची पर जिसे जारी करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के कंधों पर है। यह सूची सिर्फ नामों का संग्रह नहीं होगी बल्कि यह तय करेगी कि लोकतंत्र की



इस लड़ाई में कौन मजबूती से खड़ा रहेगा और कौन इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या इस सूची के बाद बंगाल की सत्ता का समीकरण बदल जाएगा? क्या यह दस्तावेज किसी राजनीतिक दल के लिए विजयपत्र बनेगा या किसी के लिए अस्तित्व का संकट?

बीजेपी का गणित सियासत बनाम सिस्टम

बीजेपी की रणनीति साफ है मतदाता सूची में कथित अवैध नामों को हटाकर अपने कोर वोट बैंक के अनुपात को मजबूत करना। यह वही रणनीति है जो असम और अन्य राज्यों में देखी गई थी। लेकिन बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। यहां की राजनीति भावनात्मक जुड़ाव, क्षेत्रीय अस्मिता और नेतृत्व के करिश्मे पर टिकी है। ममता बनर्जी ने इस लड़ाई को



जमीनी स्तर पर बीजेपी पीछे

दूसरी ओर बीजेपी का मरोसा केटीय एजेंडिया, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और अपने बढ़ते जनाधार पर टिका है। लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी को अभी भी उस मरोसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो ममता बनर्जी ने अपने पीड़ित बनाम सत्ता वाले नेटवर्क से हासिल किया है।

प्रशासनिक प्रक्रिया से निकालकर बंगाल बनाम

बाहरी ताकत का रूप दे दिया है। उन्होंने हर मंच से

यह संदेश दिया कि यह सिर्फ नाम हटाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि बंगाल की पहचान को कमजोर करने की कोशिश है। बीजेपी का गणित आंकड़ों पर आधारित

है। लेकिन ममता की रणनीति भावनाओं पर आधारित है और बंगाल की राजनीति में अक्सर भावनाएं गणित को हरा देती हैं।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

मोदी का इजरायल दौरा आग के दरिया में कूटनीति

दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिम एशिया में मिसाइलें सिर्फ सीमाएं नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की साख भी भेद रही हैं। ऐसे विस्फोटक माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा महज एक राजनयिक कार्यक्रम भर नहीं रह जाता बल्कि यह भारत की दशकों पुरानी संतुलित विदेश नीति की सबसे कठिन परीक्षा भी बन गया है। सवाल सीधा है क्या यह यात्रा रणनीतिक मजबूरी है या कूटनीतिक जोखिम? भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक स्वायत्तता रही है। भारत ने हमेशा अमेरिका और रूस, दोनों से संबंध बनाए रखे। भारत ने ईरान से ऊर्जा ली और अरब देशों से आर्थिक साझेदारी मजबूत की, वहीं इजरायल से रक्षा तकनीक हासिल की। यही संतुलन भारत को वैश्विक मंच पर भरोसेमंद और स्वतंत्र शक्ति बनाता रहा।

लेकिन जंग जैसे माहौल में किसी एक पक्ष की यात्रा, चाहे वह प्रतीकात्मक ही क्यों न हो, संदेश स्पष्ट देती है। यह संदेश सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे अरब जगत और मुस्लिम देशों तक जाता है, जहां लाखों भारतीय काम करते हैं और जहां से भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आता है। कूटनीति में सिर्फ कदम नहीं, बल्कि उसकी टाइमिंग भी संदेश देती है। जब मिसाइलें चल रही हों, जब वैश्विक समुदाय संयम की अपील कर रहा हो, तब एक युद्धग्रस्त देश की यात्रा समर्थन का प्रतीक मानी जाती है। यह वही भारत है जिसने हमेशा शांति, संवाद और तटस्थता की बात की। आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह दौरा भारत की उस नैतिक स्थिति को कमजोर करेगा, जिसके कारण भारत को विश्वसनीय मध्यस्थ माना जाता था? क्या भारत अब मध्यस्थ की जगह एक पक्ष के सहयोगी की भूमिका में दिखेगा? भारत की ताकत उसकी स्वतंत्रता रही है उसकी पहचान उसका संतुलन रहा है। यदि यह संतुलन टूटता है तो भारत सिर्फ एक और शक्ति बन जाएगा। लेकिन वह नैतिक और कूटनीतिक ऊंचाई खो देगा जिसने उसे दुनिया में अलग स्थान दिया। आज जरूरत हथियारों के सौदों से ज्यादा कूटनीतिक संतुलन बचाने की है। क्योंकि युद्ध खत्म होते हैं लेकिन कूटनीतिक फैसलों के परिणाम दशकों तक पीछा करते हैं।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

कट्टर दक्षिणपंथ की तरफ खिसकती धुरी

गुरुबचन जगत

मनुष्य के विकास क्रम में 'नियंत्रित आग' की क्षमता हासिल करना शायद सबसे अहम पलों में एक था, क्योंकि एक बड़े आकार का दिमाग होने एवं जटिल गणना करने की उसकी क्षमता के लिए ईंधन के रूप में जितनी मात्रा में कैलोरी की जरूरत होती है, वह पका हुआ भोजन मिलने से संभव हुआ (इंसानी दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा खर्च करता है)। ऐसा माना जाता है कि आग ने इंसानों की भोजन हजम करने वाली क्षमता बढ़ाने में मदद की, जिसके अभाव में अन्य जीव-जंतुओं के दिमाग छोटे रह गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैविक मानव-विज्ञान के प्रोफेसर रिचर्ड रैंगहम ने इसे 'कुकिंग हाइपोथिसिस' का नाम दिया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के जिन पूर्वजों ने 'नियंत्रणयुक्त आग' की सामर्थ्य विकसित की, वे न केवल अपने समय के बल्कि सर्वकालिक खोजकर्ता/वैज्ञानिक गिने जाएंगे।

ऋग्वेद की सर्वप्रथम पंक्ति है 'अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवामृत्विजम्, होतारं रत्नधातमम्' अर्थात् 'अग्नि की मैं आराधना करता हूँ, वह जो ईश्वर के सम्मुख प्रज्वलित है, देवता जो देखता है सत्य को, योद्धा, और है भरपूर आनंद प्रदाता।' यह अग्नि देव का आह्वान है, जिसमें उनकी स्तुति मनुष्य और दिव्य ऊर्जा के बीच माध्यम के रूप में की गई है। 'नियंत्रणयुक्त आग' और पके भोजन की बदौलत इंसान की सूझबूझ खोज एवं आविष्कार करने में तरक्की करती गई। हालांकि, मध्य युग के महान वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने जबरदस्त तरक्की की थी, तथापि बड़ी छलांग औद्योगिक क्रांति के समय लगी, जिसके दौरान इंसानी सूझबूझ एवं आविष्कारों की एक बड़ी लहर देखी गई। इसने पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक आंदोलनों को भी जन्म दिया। विज्ञान के साथ-साथ साहित्य भी फला-फूला। लोकतांत्रिक शासन और संस्थानों के विकास के कारण

औद्योगिक क्रांति के परिणाम अभी भी काफी हद तक मनुष्यता के नियंत्रण में थे। ये स्वभाव से उदार थीं, जब तक कि जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे राज्यों में तानाशाही का उदय नहीं हुआ, जिसने इन देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया।

हालांकि, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरदस्त जनसमर्थन के चलते लोकतंत्र कायम रहा। इस समय ने अगली बड़ी छलांग देखी-आण्विक ऊर्जा, जिसने सांस थामे बैठी दुनिया पर कहर बरपा दिया। सौभाग्य से, दुनिया में सहमति बनी और इस ऊर्जा को



नियंत्रण में रखने के लिए संस्थान बनाए गए। परमाणु संपन्न शक्तियों ने संधियों पर हस्ताक्षर किए और उनपर अमल किया। अब तक तो हम कामयाब रहे हैं और इसका इस्तेमाल अधिकांशतः सकारात्मक तरीके से होता आया है। ऐसा हमारे लोकतंत्रों, उदारवादी सरकारों और संस्थानों की वजह से संभव हो पाया। आज जब इंसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने में लगा है और चूंकि ये दोनों साथ मिल रहे हैं, ऐसे में 'सेटिंग' एआई (चेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की तगड़ी संभावना है। सैद्धांतिक तौर पर यह ऐसा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) है जो स्वयं सोच-विचार कर सके और अपने फैसले खुद ले सके। क्या हम एक बार फिर से अहम मोड़ पर हैं... क्या मनुष्य अगली 'नियंत्रित आग' विकसित करने ही वाला है? तकनीक के विकास के साथ-साथ मानवता के विकास के लिए सदा से चुनौती रही है कि पैदा की गई आग को

'काबू में कैसे रखा जा सके', क्योंकि नियंत्रण न रहने पर यह तबाही मचा देगी। चेर्नोबिल और अन्य न्यूक्लियर आपदाएं इसका एक उदाहरण हैं, इतने ही 'हिरोशिमा' और 'नागासाकी' पर बम गिराने जैसे कृत्य भी। इसी प्रकार, कोविड महामारी के बारे में कई सवाल अनसुलझे हैं, तकनीक के गलत इस्तेमाल के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, कि कैसे अपने फायदे के लिए बनाई गई तकनीक को मनुष्य जनसंहार करने का हथियार बनाने अथवा फिर दूसरों पर नियंत्रण बनाने में बदल देता है। क्योंकि जब हम इतनी आधुनिक तकनीक बना

रहे हैं, तब हमें कार्ल सैगन की दी संज्ञा 'तकनीक की किशोरावस्था' को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें अपनी खासियत के अनुसार, इंसान के पास दुनिया बदलने की जबरदस्त ताकत तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल समझदारी या दूरदर्शी से करने की अक्लमंदी नहीं है।

आज यह गौरतलब है कि धुरी ठेठ दक्षिणपंथ की तरफ सरक रही है, इसे अमेरिका को पुनः महान बनाओ (मागा) अभियान और यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका वगैरह में इस किस्म की राजनीतिक लहरों में देखा जा सकता है। हमारी महान तकनीकी तरक्की ऐसे वक्त में हो रही है जब राजनीति एवं सरकार में उदारवाद की जगह ठेठ दक्षिणपंथ लेता जा रहा है। उदारवादी लोकतंत्र और उदारवादी अर्थव्यवस्था की जगह अधिनायकवादी राजनीति और अर्थव्यवस्था लेती जा रही है... विश्व व्यवस्था फिर से राष्ट्रवादी राज्य की तरफ लौट रही है।

लेफ्टिनेंट जनरल एसएस मेहता सेवानिवृत्त

युद्ध का शब्दिक अर्थ अपनी परिभाषा से बाहर निकल चुका है। सदियों से, शक्ति का माप हल की नोक और युद्धपोत के पीछे बने वाली लहरों से किया जाता रहा है। रणनीति ने भूमि, समुद्र, वायु, शांत गहराइयों, अंतरिक्ष के निर्वात और साइबर गिड की टिमटिमाती शिराओं का मानचित्रण कर लिया है। आज एक सातवें कार्यक्षेत्र (डोमेन) ने चुपचाप रणनीति की धुरी को हर लिया है। एक अनुभूति सबसे अंतरंग और सबसे व्यापक। यह बदलाव अब और अधिक सैद्धांतिक नहीं रहा। पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया तक और हमारी अपनी विवादित सीमाओं पर, युद्ध का दायरा पहले ही विस्तृत हो चुका है। प्रभाव अभियान अब प्रत्यक्ष कार्रवाई से पहले, उसके साथ और उसके बाद तक जारी रहता है। केंद्र बिंदु अब मंचों से धारणा की तरफ सरक रहा है, केवल मारक क्षमता से हटकर एकजुटता कायम रखने वाला समाज ही तनाव के दौरान बचा रह सकता है।

आधुनिक युद्धक्षेत्रों में, नैरेटिव की गति, सूचनागत आघात और सामाजिक लचीलेपन के जरिए परिणाम निरंतर आकार लेते जा रहे हैं। धारणा ने अब ओओडीए लूप्स, एस्केलेशन थ्रेशोल्ड और राजनीतिक निर्णय चक्रों को इस प्रकार संकुचित कर दिया है, जिसका अनुमान परंपरागत सिद्धांत पूरी तरह लगा नहीं पाए। एकजुट रखने वाला कार्यक्षेत्र राष्ट्र शक्ति का शून्य-शून्य, भारतीय सभ्यता का एक योगदान, गणित में वह मूक गुणांक है जो पैमाना बनाता है। किसी राष्ट्र की संरचना में सामाजिक सामंजस्य वही बुनियादी भूमिका निभाता है। इस शून्य के बिना, शक्ति का अंकगणित अस्थिर हो जाता है। इसके बगैर, सबसे उन्नत गतिज ताकतें, मिसाइलें, उपग्रह और विमान

संज्ञानात्मक युद्ध : दांवपेच का सातवां रणक्षेत्र



वाहक बेड़े तक भी आकर्षण खो देते हैं। जब सामाजिक विश्वास भंग हो जाए, तो सैन्य क्षमता थम जाती है। जब दोनों एकीकृत हो जाएं, तो राष्ट्रीय शक्ति अधिक वेग से आगे बढ़ती है। इसलिए संज्ञान आधुनिक युद्धों में जोड़ने वाले डोमेन के रूप में उभरा है। इसकी एक सतह पर लोगों में एकता निहित है; दूसरी सतह पर युद्ध के छह पारंपरिक माध्यम संचालित होते हैं।

प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, लेकिन उनकी असली क्षमता एकीकरण में निहित है। सातवें कार्यक्षेत्र में एकता वह जोड़ने वाला पदार्थ है जो सबको थामे रखता है। नदी का सिद्धांत क्षरण से घेराबंदी तक - भारत ने 1971 के युद्ध में इस गतिशीलता का आरंभिक प्रदर्शन देख लिया था। 'मेघना क्रॉसिंग', एक दुस्साहसिक नदी पारीय अभियान, जिसने ढाका के लिए राह खोल दी, इसने बलों की तैनाती से कहीं अधिक किया। इसने प्रतिद्वंद्वी की अपरिहार्यता की धारणा को बदलकर रख दिया। जलीय बाधा के तर्क ने आगे बढ़ने की संभावना को खारिज कर रखा था, लेकिन वायुसैन्य प्रहारों और बख्तरबंद दस्तों वाले अभियान ने संज्ञानात्मक अनुभूति

आघात दिया। प्रतिद्वंद्वी के पास गोला-बारूद खत्म नहीं हुआ था; बल्कि लड़ने की इच्छाशक्ति उखड़ गई थी। इस संज्ञानात्मक आघात ने आत्मसमर्पण गति को तीव्रता दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, 'मेघना सिद्धांत' पुनः तीव्र प्रासंगिकता प्राप्त कर गया है।

सातवें डोमेन में, उद्देश्य संज्ञानात्मक घेराबंदी बनाना है- प्रतिद्वंद्वी द्वारा भंग करने से कहीं पहले, अपने प्रणालीगत संतुलन की संभाल लेना। यह लाभ संकट के दौरान कभी भी सुधारा नहीं जा सकता; इसे युद्धों के बीच के काल में निरंतर, कल्पनाशील प्रशिक्षण के माध्यम से ढालना पड़ता है। भारत की संरचनात्मक उत्कृष्ट कृति वितरित लचीलापन- अधिकांश आधुनिक शक्तियां किले जैसी हैं, केंद्रीकृत, भव्य, और अक्सर भंगुर। भारत अलग ढंग से विकसित हुआ है। यह एक जीवंत नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। संविधान की प्रस्तावना सोर्स कोड के रूप में कार्य करती है। बहुलवाद उच्च स्तरीय झटका-अवशोषक के रूप में कार्य करता है। 'अनेकता में एकता' महज बयानबाजी के रूप में नहीं बल्कि वितरित रक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। चुनावी मंथन, भाषाई

बहुलता और संघीय जटिलता गणतंत्र पर बार-बार दबाव डालकर इसका इम्तिहान लेती है। रणनीतिक गहराई उस संचित अनुभव से बनी है। 1.4 अरब अलग-अलग स्वयं का एक देश, जो लोकतांत्रिक सहमति से जुड़ा हुआ है, वह सूचनात्मक झटकों का असामान्य रूप से शक्तिशाली अवशोषक बन जाता है। वह शक्ति जो सामाजिक रूप से स्थिर नहीं होती, वह रणनीतिक रूप से नाजुक हो जाती है। 1962 के बाद का हर युद्ध इस सहनशक्ति का गवाह है। एआई का दौर और डिजिटल ढांचा- कृत्रिम बुद्धिमत्ता धारणा और प्रतिक्रिया के बीच अंतराल को कम कर रही है।

ऐसे माहौल में विश्वसनीयता खुद-ब-खुद युद्धक शक्ति का एक रूप बन जाती है। ड्रोन एक हवाई मशीन है, संज्ञान माध्यम है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढांचा जनता के स्तर पर विश्वास निर्माण हेतु पहले से बना बनाया सांचा प्रदान करता है। सही ढंग से संचालित, ऐसे मंच सुनिश्चित कर सकते हैं कि धारणा और सत्यापन योग्य वास्तविकता के बीच अंतर खतरनाक रूप से न बढ़ने पाए। यूक्रेन - एक तनाव परीक्षा- यूक्रेन-रूस संघर्ष सातवें डोमेन का तनाव के दौरान गहराई से परीक्षा का अवसर प्रदान करता है। सालों से जारी युद्ध में, अकेले युद्धक्षेत्र प्रदर्शन ने रणनीतिक सहनशीलता का निर्धारण नहीं किया है। नैरेटिव सुसंगतता, आर्थिक सहनशक्ति और राजनीतिक वैधता परंपरा को जारी रखे हुए है। जो चीज लगातार दिखाई दे रही है, वह है लंबे समय से तनाव के बीच भी सामाजिक एकता की धुरी कायम रहना। जो राष्ट्र आंतरिक विश्वास बनाए रखेंगे, वे उद्देश्य पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं; जहां पर परस्पर भरोसा खंडित हो जाए, वहां पर रणनीतिक हानि जमा होती जाती है।

होली के त्योहार पर ऐसे बनाएं

आलू के पापड़

होली का त्योहार रंगों के साथ-साथ स्वादिष्ट पकवानों के लिए भी जाना जाता है। इस मौके पर घरों में तरह-तरह की पारंपरिक चीजें बनाई जाती हैं, जिनमें आलू के पापड़ का खास स्थान है। बाजार में मिलने वाले पापड़ जहां महंगे और मिलावटी हो सकते हैं, वहीं घर पर बनाए गए आलू के पापड़ स्वाद, शुद्धता और सेहत तीनों के लिहाज से बेहतर होते हैं। खास बात ये है कि सही तरीके से बनाए गए आलू के पापड़ लंबे समय तक खराब नहीं होते और सालभर आराम से खाए जा सकते हैं। तो अगर आप भी होली की तैयारियों के दौरान कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ टिकाऊ भी हो, तो आलू के पापड़ एक बेहतरीन विकल्प हैं। तो आप कम समय और कम सामग्री में परफेक्ट आलू के पापड़ बना सकती हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे।



विधि

सबसे पहले 2 किलो अच्छे और बिना दाग वाले आलू लें। आलुओं को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर या बड़े बर्तन में पूरी तरह गलने तक उबाल लें। ध्यान रखें कि आलू ज्यादा पानी वाले न हों, वरना पापड़ ठीक से सूखेंगे नहीं। उबलने के बाद आलुओं को ठंडा करें और छीलकर किसी बड़े बर्तन में अच्छी तरह मेश कर लें। इस बात का खास ध्यान रखें कि मिश्रण में एक भी गुठली न रहे, वरना पापड़ बेलते समय टूट सकते हैं। अब मेश किए हुए आलू में स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन डालें। चाहे तो आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी मिला सकती हैं। सभी मसालों

सामग्री

आलू- 2 किलो, नमक- स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर- 2 चम्मच, जीरा पाउडर- 1 चम्मच, अजवाइन- 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर- आधा चम्मच।

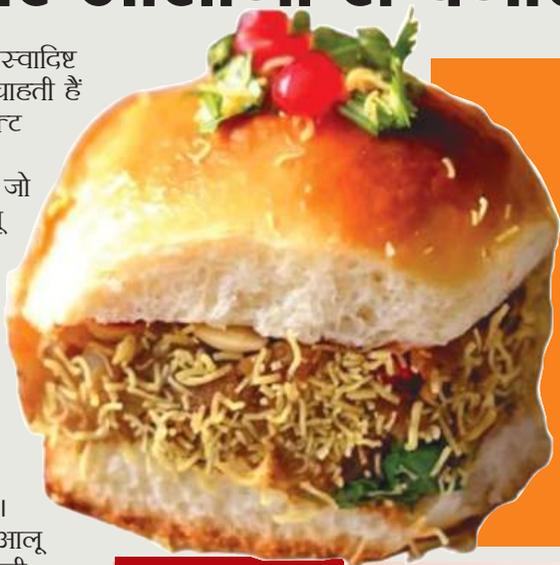


बिल्कुल न डालें। इसके बाद मिश्रण से नींबू के आकार के छोटे-छोटे गोले बना लें। किसी साफ प्लास्टिक शीट या सूती कपड़े पर गोले रखकर हल्के हाथ से बहुत पतले पापड़ बेलें। पापड़ जितने पतले होंगे,

उतने ज्यादा कुरकुरे बनेंगे। अब इन पापड़ों को तेज धूप में 2 से 3 दिन तक सुखाएं। रोज उन्हें पलटते रहें ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाएं। जब पापड़ पूरी तरह सख्त हो जाएं और हाथ लगाने पर टूटने लगें, तब इन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें। सही तरीके से बनाए और सुखाए गए आलू के पापड़ सालभर तक खराब नहीं होते और जरूरत पड़ने पर तलकर या सेककर खाए जा सकते हैं।

वीकेंड पर आसानी से बनाएं दाबेली

वीकेंड पर अगर कुछ स्वादिष्ट और आसान बनाना चाहती हैं तो दाबेली एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये एक स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है, जो अपने मसालेदार आलू स्टफिंग और मीठी-खट्टी चटनी के लिए मशहूर है। घर पर इसे बनाना न केवल मजेदार होता है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी एक अलग अनुभव देता है। दाबेली में मसालेदार आलू मिश्रण, इमली की चटनी, मूंगफली, और ताजी हरी धनिया का इस्तेमाल होता है, जो इसे हर बाइट में स्वाद का धमाका बना देता है। इसे ब्रेड या छोटे बन्स में भरकर ताजा तैयार किया जाता है और सर्विंग के समय थोड़ी हरी चटनी या हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है। इसलिए घर पर स्वादिष्ट और परफेक्ट दाबेली आसानी से तैयार करें और ये हर किसी को पसंद आएंगे।



सामग्री

4-5 मध्यम आकार के उबले आलू, लाल मिर्च पाउडर - 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला- 1/2 छोटा चम्मच, नमक - स्वाद अनुसार, छोटे पाव- 6-8, मूंगफली - 2 बड़े चम्मच (भुनी हुई), ताजा हरा धनिया - 2 बड़े चम्मच (कटा हुआ), सेव - 2 बड़े चम्मच, मीठी चटनी, हरी चटनी।

विधि

सबसे पहले आलू को अच्छी तरह उबाल लें और पूरी तरह मेश कर लें। मेश किए हुए आलू में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक मिलाएं जब तक मसाले पूरी तरह से आलू में घुल न जाएं। इसके बाद चटनी

तैयार करें। मीठी चटनी के लिए इमली का पेस्ट और गुड़ या शक्कर को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा मिश्रण बनाएं। हरी चटनी बनाने के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस और नमक को मिक्सी में पीसकर स्मूद पेस्ट तैयार करें। अब ब्रेड बन्स को बीच से हल्का काटें और अंदर मसालेदार आलू भरें। आलू को ब्रेड के अंदर अच्छी तरह सेट करें ताकि भरावन

फैल न जाए। उसके ऊपर थोड़ी भुनी हुई मूंगफली, ताजा हरा धनिया और कंची सेव डालें। तैयार दाबेली को तुरंत परोसें ताकि ब्रेड नरम रहे और मसाले का स्वाद ताजा रहे। चाहे तो इसे हरी चटनी या मीठी इमली की चटनी के साथ परोसें। दाबेली को स्नैक के रूप में या वीकेंड स्पेशल फूड के तौर पर परिवार और दोस्तों के साथ एन्जॉय किया जा सकता है।



हंसना मना है

प्रेमिका- तुमको पता है कल मेरा बर्थडे है? मुझे क्या गिफ्ट दोगे? प्रेमी- जो तुम चाहो.. प्रेमिका- रिंग? प्रेमी-ठीक है रिंग दूंगा पर उठाना मत, बैलेंस बहुत कम है।

दो पंडितों में लड़ाई हो रही थी, उन्हें लड़ते बहुत देर हो गयी, तीसरा पंडित- क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? एक पंडित बोला, जब मैं लहसुन, प्याज नहीं खाता, तो इस साल ने चिकन में डाला ही क्यों?

एक बार किसी ने पूछा की ये शादी कब

होती है? जवाब ये था की जब आपका समय अनुकूल ना हो, राहु-केतु और शनि की दशा खराब हो, आपका मंगल कमजोर हो और भगवान ने भी आपकी मजे लेने की टान ली हो। उस समय शादी हो जाती है!

पति- काश! मैं गणपति होता, तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मजा आता.. पत्नी: हा, काश तुम गणपति होते, मैं रोज लड्डू खिलाती, और हर साल विसर्जन करके नए गणपति घर लाती, बड़ा मजा आता..!

कहानी

लक्ष्य पर ध्यान

यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक दिन वो सैर के लिए निकले और घूमते-घूमते एक पुल के पास पहुंचे। तभी उनकी नजर पुल पर खड़े बच्चों पर गई। सभी बच्चे बंदूक से पुल के नीचे बहती बड़ी-सी नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वो एक बार भी अंडे के छिलके पर सही निशाना नहीं लगा पाए। यह देखकर स्वामी विवेकानंद बड़े हैरान हुए। उनके मन में हुआ कि मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से बंदूक मांगी और खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी ने बंदूक तानी और अंडे के छिलके पर पहली बार में ही निशाना लगा लिया। पहला निशाना सही लगाने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे अंडे के छिलकों पर सही निशाना लगाया। स्वामी के निशाने की कला को देखकर बच्चे हैरान रह गए। बच्चों ने स्वामी से पूछा कि आखिर वो कैसे एक के बाद एक सही निशाना लगा रहे हैं। आगे बच्चों ने कहा कि वो बहुत देर से उन छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमें भी बताइए सही तरीके से निशाना लगाने के लिए क्या करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, जो किया नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस अपना सारा ध्यान उस काम की तरफ लगाओ, जिसे तुम्हें करना है या जिसे तुम कर रहे हो। उन्होंने आगे बताया कि अगर निशाना लगाते वक्त तुम्हारा सारा ध्यान अंडे के छिलके पर होता, तो तुम निशाना ठीक तरीके से लगा पाते।

कहानी से सीख- लक्ष्य को पूरा करने की चाहत रखने वाले को हमेशा पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य चूकता नहीं है।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

पंडित संदीप आनंद शर्मा

<p>मेष</p>  <p>रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। कार्य की प्रशंसा होगी। प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी। यात्रा मनोरंजक हो सकती है। व्यापार-व्यवसाय में नए प्रयोग किए जा सकते हैं।</p>	<p>तुला</p>  <p>यात्रा मनोनुकूल रहेगी। नया काम मिलेगा। नए अनुबंध होंगे। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा।</p>
<p>वृषभ</p>  <p>विवाद को बढ़ावा न दें। बेवजह कहासुनी हो सकती है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। थकान व कमजोरी रह सकते हैं। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।</p>	<p>वृश्चिक</p>  <p>कार्यस्थल पर सुधार व परिवर्तन हो सकता है। योजना फलीभूत होगी। तत्काल लाभ नहीं होगा। निवेश में जल्दबाजी न करें। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं।</p>
<p>मिथुन</p>  <p>मित्रों का सहयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल चलेगा। शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड से लाभ होगा।</p>	<p>धनु</p>  <p>अध्यात्म में रुझान रहेगा। सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। राजकीय बाधा दूर होकर स्थिति लाभदायक बनेगी। निवेश में जल्दबाजी न करें। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं।</p>
<p>कर्क</p>  <p>आत्मसम्मान बना रहेगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले-बिसरे साधियों व संबंधियों से मुलाकात होगी। कारोबार में अनुकूलता रहेगी।</p>	<p>मकर</p>  <p>स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि की आशंका बनती है, सावधानी आवश्यक है। लेन-देन में जल्दबाजी से बचें।</p>
<p>सिंह</p>  <p>बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।</p>	<p>कुम्भ</p>  <p>कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा।</p>
<p>कन्या</p>  <p>स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। फालतू खर्च होगा। कर्ज लेना पड़ सकता है।</p>	<p>मीन</p>  <p>भूमि-भवन व मकान-दुकान इत्यादि की खरीद-फरोख्त मनोनुकूल लाभ देगी। बेरोजगारी दूर होगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा।</p>

रो हित शेव्ठी की फिल्म गोलमाल 5 में हाल ही में अजय देवगन, अरशद वारसी, कुणाल खेमू और श्रेयस जैसे सितारों से सजी स्टार कास्ट में अक्षय कुमार का नाम जुड़ने की खबर सुर्खियों में थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म में अब एक साउथ एक्ट्रेस के जुड़ने की भी जानकारी सामने आई है।

गोलमाल 5 की शूटिंग शुरी हो चुकी है और पहले शेड्यूल में ज्यादातर मुख्य कलाकार मौजूद थे। अजय देवगन भी जल्द ही शूटिंग में शामिल हो जाएंगे।

गोलमाल 5 की शूटिंग कहां शुरू हुई है, इसकी

गोलमाल 5 में नजर आएंगी दक्षिण अभिनेत्री प्रियामणि



जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। गोलमाल 5 की टीम में एक नया

चेहरा जुड़ गया है। जानकारी के अनुसार, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रियामणि अब गोलमाल 5 में नजर आएंगी। प्रियामणि साउथ की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। बहरहाल, प्रियामणि का रोल क्या होगा, ये अभी सीक्रेट है, लेकिन उन्होंने अपनी शूटिंग शुरू कर

प्रियामणि के बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स

प्रियामणि ने कई चर्चित बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिनमें वेब सीरीज द फैमिली गैज और शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान शामिल है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म आर्टिकल 370 में भी अभिनय किया है। वह हिंदी सिनेमा में चैनल एक्सप्रेस (डांस नंबर) और गणितरत्न की फिल्म रावण (केनियो) का भी हिस्सा रही हैं।

दी है। पहला शेड्यूल करीब एक महीने चलेगा। पहले से ही खबर थी कि अक्षय कुमार भी फिल्म में होंगे। वो अजय देवगन और उनके गैंग के साथ कॉमेडी में धमाल मचाएंगे। पुराने कलाकार जैसे अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और अधिनी कालसेकर भी वापस आ रहे हैं। लेकिन शायद करीना कपूर खान इस बार फिल्म में नहीं होंगी।

बॉलीवुड

मन की बात

मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूँ: संजय लीला भंसाली



सं

जय लीला भंसाली को इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन और विजयनरी डायरेक्टरों में से एक माना जाता है। वो अपनी फिल्मों की भव्यता और कहानी कहने के अंदाज से इंडियन फिल्मों को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए जाने जाते हैं। कई सुपरहिट क्लासिक फिल्मों देने के बाद, अब वो अपने करियर के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक, लव एंड वॉर की तैयारी कर रहे हैं। इस ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा में पहली बार बॉलीवुड के बड़े सितारे आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे। दर्शक इस फिल्म की थिएटर रिलीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने जन्मदिन पर भी भंसाली ने सेट पर ही रहना पसंद किया और पूरी तरह लव एंड वॉर के काम में डूबे रहे। अपने जन्मदिन पर काम करने को लेकर उन्होंने कहा, काम ही वो चीज है जिससे मेरी पहचान बनती है। जब मेरे पास काम नहीं होता, तो मुझे खुद की कोई वैल्यू महसूस नहीं होती। एक आर्टिस्ट के तौर पर अब मैं पहले से ज्यादा निडर हो गया हूँ और रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आज मैं 5 या 10 साल पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूँ और मुझे इसमें मजा आ रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी न देते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ कुछ खास करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाल ही में, संजय लीला भंसाली ने लव एंड वॉर के लिए दो बहुत बड़े म्यूजिकल सीकेंस शूट किए हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। अपनी ग्रैंड विजुअल स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर भंसाली ने यह पक्का किया है कि इन गानों की कोरियोग्राफी शानदार हो, मूवमेंट्स दमदार हों और स्टेजिंग बिल्कुल नई हो, जो फिल्म की वॉर-एरा लव ट्रायंगल वाली इमोशनल कहानी से गहराई से जुड़ी हो। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसी पावरहाउस तिकड़ी के साथ भंसाली के हाथ मिलाने की खबर ने जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में इस बड़े कोलेबोरेशन को अभी से सिनेमा की एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा रहा है।

रणवीर सिंह की प्रलय में भाग्यश्री बोरसे को मिली एंट्री

रणवीर सिंह इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ उनकी फिल्म धुरंधर : द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी हलचल तेज है। इसी बीच उनकी नई फिल्म प्रलय को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

खबर है कि इस जॉम्बी एक्शन फिल्म में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है, जो कल्याणी प्रियदर्शन को कड़ी टक्कर देती नजर आएंगी।

बता दें, पहले ही फिल्म में कल्याणी

प्रियदर्शन को फीमेल लीड के तौर पर साइन किया जा चुका है। लेकिन अब खबर आ रही है कि दूसरी अहम भूमिका के लिए भाग्यश्री बोरसे को फाइनल कर लिया गया है। हालांकि मेकर्स ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है,

लेकिन इंडस्ट्री में यह खबर तेजी से फैल रही है। भाग्यश्री बोरसे साउथ इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं और अब प्रलय उनके

करियर का सबसे बड़ा हिंदी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मेकर्स ने फिल्म में बड़े चेहरों की बजाय नए कलाकारों को मौका देने की कोशिश कर रही है। इससे फिल्म में ताजगी देखने को मिल सकती है। कहानी जॉम्बी हमले के बीच इंसानी जंग और जच्चे को दिखाएगी। यानी सिर्फ डर नहीं, बल्कि इमोशन और संघर्ष भी कहानी का हिस्सा होंगे।

प्रलय एक बड़े बजट की जॉम्बी सर्वाइवल एक्शन फिल्म बताई जा रही है, जिसे जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले वह पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 : द हर्षद मेहता स्टोरी में को-डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।



क्या आप जानते हैं होली पर गुझिया क्यों बनती है? कहां से शुरू हुआ ये रिवाज?

जैसे-जैसे होली नजदीक आती है, पूरे उत्तर भारत के घरों में खोया, ड्राई फ्रूट्स और घी में तली गुझिया की खुशबू फैलने लगती है। गुझिया सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मेल-मिलाप और परंपरा का प्रतीक भी मानी जाती है। इतिहासकार इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग मत रखते हैं, लेकिन आम तौर पर इसकी जड़ें 13वीं से 17वीं सदी के बीच मानी जाती हैं। इतिहास में गुझिया जैसी मिठाइयों का उल्लेख 13वीं सदी में मिलता है, हालांकि उस समय इन्हें तला नहीं जाता था। गेहूं के आटे की लोइयों में गुड़ और शहद भरकर धूप में सुखाया जाता था। यह सरल मिठाई बसंत के फसल उत्सवों में बनाई जाती थी, जो बाद में होली की परंपरा से जुड़ गई। कुछ फूड इतिहासकार मानते हैं कि इस मिठाई पर मिडल ईस्टर्न डेजर्ट जैसे बकलावा का प्रभाव हो सकता है। व्यापार मार्गों के जरिए सूखे मेवे और मीठी भरावन का विचार भारत तक पहुंचा होगा। वहीं एक मत इसे समोसे के मीठे रूप से जोड़ता है, जिसकी उत्पत्ति भी पश्चिम एशिया से मानी जाती है। दूसरी ओर कई विद्वान इसे पूरी तरह भारतीय मानते हैं। पुराने संस्कृत ग्रंथों में करणीका नाम की मिठाई का उल्लेख मिलता है, जिसमें शहद और मेवे भरे जाते थे। इसे आधुनिक गुझिया का प्रारंभिक रूप माना जाता है। मुगल काल, खासकर 16वीं-17वीं सदी में, गुझिया का स्वरूप काफी बदल गया। इस दौर में खोया, चीनी और सूखे मेवों की भरावन लोकप्रिय हुई और घी में तलने की परंपरा भी प्रचलित हो गई। होली से इसका संबंध खासतौर पर उत्तर भारत में मजबूत हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र को होली पर गुझिया बनाने की परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वहीं ब्रज और वृंदावन का इससे गहरा नाता है। राधा रमण मंदिर में सदियों से भगवान श्री कृष्ण को गुझिया और चंद्रकला का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा रही है। चूंकि होली राधा-कृष्ण की कथाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए समय के साथ गुझिया इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा बन गई।



अजब-गजब अपने कर्मचारी को बचाने के लिए कंपनी ने दिखायी दरियादिली

मेक्सिको में भड़की हिंसा के बीच अपने एक कर्मचारी को बचाने के लिए कंपनी ने खरीद ली सभी फ्लाइट टिकटें

मेक्सिको में उस समय हड़कंप मच गया जब कुख्यात ड्रग सरगना Nemesio Oseguera Cervantes उर्फ 'एल मेंचो' के मारे जाने की खबरें फैलने लगीं। वह Jalisco New Generation Cartel का प्रमुख माना जाता है। जैसे ही यह खबर वायरल हुई, कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। सड़कों पर जाम लग गया, उड़ानें रद्द होने लगीं और हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

एयरपोर्ट पर मची दहशत: Guadalajara International Airport पर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच अमेरिका की क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी Vercel का कर्मचारी एंड्रयू बार्बा अपनी पत्नी के साथ वहां फंस गया। वहां हिंसा और आगजनी का माहौल था। बार्बा खुद को और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

बचने के लिए छिपना पड़ा वॉशरूम में: स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए एयरपोर्ट के वॉशरूम में शरण लेनी पड़ी। इंटरनेट सेवाएं बाधित थीं और ज्यादातर प्लाइड्स रद्द हो चुकी थीं। बाहर बढ़ती हिंसा और अनिश्चितता ने



यात्रियों की चिंता और बढ़ा दी थी। कंपनी ने बुक कर ली सारी टिकट: सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी की लीडरशिप टीम ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ग्वाडालाहारा से अमेरिका जाने वाली हर उपलब्ध फ्लाइट की टिकट बुक कर ली, ताकि कम से कम एक विमान उड़ान भर सके और उनके कर्मचारी सुरक्षित निकल सकें।

'प्लान बी' और 'प्लान सी' भी थे तैयार: यह उनका 'प्लान ए' था, जबकि जरूरत पड़ने पर 'प्लान बी' और 'प्लान सी' भी तैयार थे। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। एंड्रयू बार्बा अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित डलास पहुंच गए। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट कर अपनी कंपनी का आभार जताया।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के चलते घटे कपास के दाम!

» मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष का दावा- 11 फीसदी तक गिर गये कपास के भाव

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा है कि इस समझौते के बाद मध्य प्रदेश में कपास के दामों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। वह यहां किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि अमेरिका के साथ हुआ व्यापारिक समझौता देश के साथ मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है।

सवाल उठता है कि जब बाहर से फसल सस्ती आएगी तो क्या यहां के समर्थन मूल्य में गिरावट नहीं

होंगी। उमंग सिंघार ने कहा कि जिस दिन अमेरिका के साथ डील हुई, उसी दिन कपास के भाव 11 प्रतिशत गिर गए थे। मध्य प्रदेश के सरसों के किसानों का क्या होगा, सोयाबीन के किसानों का क्या होगा, और कपास के किसानों का क्या होगा? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा बड़ा है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में उनकी आवाज



उमंग सिंघार बोले- किसानों पर पौने दो लाख करोड़ का कर्ज

राज्य के किसानों पर पौने दो लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार इस बारे में नहीं सोचती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए मध्य प्रदेश आए हैं। किसान महापंचायत हो रही है। देश में किसान महापंचायत की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। किसान और युवा बाहर आए और इसमें साथ दें क्योंकि यह कांग्रेस की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि किसान और युवा की लड़ाई है।

कहा- यह फैसला किसानों के लिए दुखद है

को बुलंद करना चाहती है। देश का बड़ा वर्ग खेती-किसानी के काम में लगा हुआ है। यह फैसला किसानों के लिए दुखद है। सवाल उठ रहा है, क्यों केंद्र सरकार किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है? किसान पहले ही कर्ज में डूबा है।

सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड पाकिस्तान की राह मुश्किल

» हैरी ब्रूक का तूफानी शतक इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलंबो। आईसीसी टी20 विश्वकप 2026 के सुपर चरण में इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक की ऐतिहासिक शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच में इंग्लैंड ने 165 रनों का लक्ष्य 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि पाकिस्तान की राह अब बेहद कठिन हो गई है। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवर में 164 रन बनाए। पाकिस्तान की शुरुआत संतुलित रही, लेकिन टीम बड़े रकोर तक नहीं पहुंच सकी।

इंग्लैंड ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया, जिससे पाकिस्तान 170 के पार नहीं जा सका। वहीं 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने पहली

ही गेंद पर ओपनर फिल साल्ट को आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। इसके बाद शाहीन ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए दो और विकेट झटके। इंग्लैंड ने महज 35 रन के स्कोर पर अपने तीन प्रमुख विकेट गंवा दिए थे और टीम पूरी तरह दबाव में आ गई थी। मुश्किल परिस्थितियों में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 100 रनों की नाबाद पारी खेली। मैच के अंतिम ओवरों में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया था। इंग्लैंड को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के

गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार इंग्लैंड ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 5 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। वहीं पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिससे उसे केवल एक अंक मिला था। अब इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर हो गया है।



वर्ल्डकप बीच में छोड़कर घर लौटे रिकू सिंह

नई दिल्ली। भारत के स्टार बल्लेबाज रिकू सिंह अपने घर वापस लौट गए हैं। रिकू का इस तरह से भारतीय टीम को छोड़कर वापस जाना बड़ा झटका है क्योंकि टीम इंडिया को आने वाले सभी मैचों में जीत हासिल करनी है। रिकू के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी है और इस वजह से उन्हें घर वापस लौटना पड़ा है। रिकू भारतीय टीम के साथ कब जुड़ेगे, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। रिकू टीम इंडिया के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच की तैयारी के लिए चेन्नई में मौजूद थे। हालांकि, अचानक उन्हें पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली और उन्हें केम छोड़कर अपने घर वापस लौटना पड़ा। सामने आई जानकारी के मुताबिक उनके पिता को चौथे स्टेज का लिवर कैंसर है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वे वेंटिलेटर पर हैं। उम्मीद है कि वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे सुपर-8 मैच से पहले भारतीय टीम में शामिल हो जाएंगे।

उदय भानु चिब की मां ने प्रदर्शन को बताया लोकतांत्रिक अधिकार

» कहा- देश तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ शर्मसार

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित हुए एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर बवाल जारी है। इस बीच पटियाला कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को मंगलवार को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है और सत्ताधारी एनडीए सरकार पर जानबूझकर तानाशाही रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगा रही है। इस बीच उदय भानु चिब की मां रजनीबाला ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन को साजिश बताया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देश में विरोध करना कब से साजिश होने लगा।

संविधान में हमें हक दिया गया है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे, तो

रमजान में मिले सरकारी कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी: एआईएमआईएम

» पूर्व में पार्टी रमजान में शराब की दुकानों को बंद करने की उठा चुकी है आवाज

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एआईएमआईएम की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमई ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस से जल्दी छुट्टी देने की मांग की है। शोएब ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हमारी मांग पर गौर करना चाहिए। जमई ने कहा कि रमजान में सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों की इच्छा होती है कि वह अपने घर पहुंचकर इफ्तार करें। दिल्ली में शाम के समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। इसलिए हमारी मांग है कि मुस्लिम कर्मचारियों को इयूटी टाइम में छूट दी जानी चाहिए ताकि वह सही समय पर अपने घर लौट सकें और इफ्तार कर सकें।

लुधियाना यूनिवर्सिटी में इफ्तार को लेकर विवाद पर एआईएमआईएम नेता ने कहा कश्मीरी स्टूडेंट्स की क्या गलती है? वह पूरे देश में पढ़ते हैं। मैंने यह साउथ इंडिया में भी देखा है और नॉर्थ इंडिया में भी वह बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। वे हमारी जामिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए रोजा और इफ्तार उनके धार्मिक काम का हिस्सा है और वे इसे रखेंगे। जब दूसरे धर्मों का सम्मान किया जाता है और मनाया जाता है तो रोजा और इफ्तार में क्या गलत है? बिहार में मीट और



जमई ने की एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा

इसी बीच शोएब जमई ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा की। शोएब ने कहा अगर कांग्रेस आलाकमान को इसकी जानकारी पहले से थी तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका निभानी है लेकिन हम अपने देश की बेइज्जती करने को बिल्कुल सही नहीं समझते हैं। शोएब जमई ने आगे कहा मैं खुद एआई समिट में गया था। मेरी टीम भी वहां थी। आप जानते हैं कि राजनीति के अलावा हम वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काम करते हैं और हमारी टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिया में काम कर रही है। इसलिए हम रिसर्च के तौर पर समिट में शामिल हुए थे। वहां जो व्यवस्था देखी हमने उसकी आलोचना की। लेकिन विदेशी मेहनतों के सामने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया आप (कांग्रेस) भी वही कर रहे हैं। वो मंच सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करने का नहीं था। विधेय प्रदर्शन की अनेकों जगह है लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह खयाल रखा जाना चाहिए।

मछली की खुली बिक्री पर बैन को लेकर शोएब जमई ने कहा कि यह मुख्य रूप से हाइजीन का मामला है। लेकिन अगर कोई मछली और मीट पर आपत्ति जताता है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि देश में लगभग 90 प्रतिशत हिंदू मछली और मीट खाते हैं।

मुंबई में दो दर्जन बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित यारी रोड इलाके में वर्षोंवा पुलिस स्टेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और पिछले कई वर्षों से मुंबई शहर में ठिकाना बनाए हुए थे। गिरफ्तार किए गए 25 लोगों में 21 ट्रांसजेंडर, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये सभी लोग देर रात यारी रोड स्थित एक दरगाह में एकत्रित होने वाले हैं। सूचना के आधार पर वर्षोंवा पुलिस की एटीसी टीम ने इलाके में छापा मारकर सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में भारतीय और बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सभी आरोपी बांग्लादेश से अवैध रूप से पहले कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद वे दिल्ली और गुजरात होते हुए मुंबई आए।



आवाज बुलंद करें। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें उदयभानु का हाथ है। वो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो यह सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा उसी के कहने पर होगा। यूथ कांग्रेस के जितने नेता हैं सभी साथ में बैठकर विचार करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। हमें पता नहीं कि सरकार ने इस घटना को दिल पर क्यों ले लिया। उन्होंने कहा कि एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन से एक दिन पहले ही पूरा देश शर्मसार हो चुका था जब गलगोटिया वालों ने चाइना के रोबोट को अपना इन्वेंशन बताकर विदेशों से आए डेलिगेट्स के सामने पेश किया।

गृह मंत्री के बिहार दौरे पर राजद का तंज

» महौल खराब करने बिहार आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तीन दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। जहां वे राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा उपायों प्रशासनिक तैयारियों और चल रही विकास पहलों की समीक्षा करेंगे। उनके बिहार दौरे से पहले ही राजद ने जोरदार तंज कसा है। राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बयान जारी करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहां साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि होली का त्योहार आ रहा है इस कारण वे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने आ रहे हैं।



भाई वीरेंद्र ने कहा कि गृहमंत्री अपना काम करने के लिए आ रहे हैं। यहां कोई घुसपैठिया नहीं है। जब जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वह इस तरह की बात करते हैं और यहां भी इस तरह का ही काम करेंगे। अगर गृहमंत्री आ रहे हैं तो उन्हें बिहार के विशेष राज्य की

सीमक्षा बैठक करेंगे शाह

वह वहां कलेक्टरों में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किशनगंज में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 26 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह अररिया जाएंगे, जहां वे लेडी सीमा चौकी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे कलेक्टरों में पुलिस अधीक्षकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के जिला अधिकारियों के साथ भारत-नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दों का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। 27 फरवरी को गृह मंत्री शाह पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बार फिर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और बैठक करेंगे।

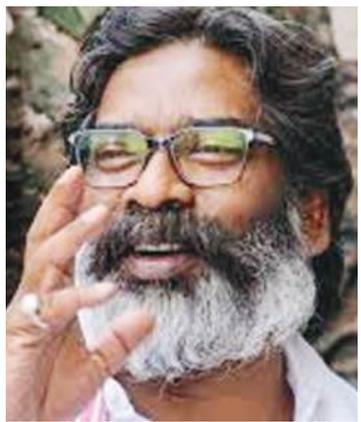
घोषणा करनी चाहिए। बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह 25 फरवरी को शाम चार बजे पूर्णिया पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा किशनगंज के लिए रवाना होंगे।

सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

ईडी के समन अवहेलना मामले में चल रही थी कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रांची। झारखंड की राजनीति में पिछले डेढ़ साल से जारी उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं बल्कि उस पूरे नैरेटिव पर सवाल है जिसमें जांच एजेंसियों की कार्रवाई को अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था।



मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने न केवल इस मामले में नोटिस जारी किया बल्कि प्रवर्तन निदेशालय को एक महत्वपूर्ण और संकेतात्मक टिप्पणी भी दी। अदालत ने हल्के लेकिन गहरे अर्थ वाले

अंदाज़ में कहा कि यह छोटा मामला है आपके पास कई बड़े मामले हैं उन पर ध्यान दीजिए। यह टिप्पणी उस संस्थागत संतुलन का संकेत है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जांच एजेंसियों को उनकी प्राथमिकताओं की याद दिला रहा है।

अधिकारों का उपयोग संतुलित तरीके से करें जांच एजेंसियां

यह टिप्पणी महज एक औपचारिक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें यह सवाल उठ रहा है कि क्या जांच एजेंसियां अपने अधिकारों का उपयोग संतुलित तरीके से कर रही हैं या राजनीतिक संदर्भों में उनका इस्तेमाल अधिक हो रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक सहयोगी के पास से कथित रूप से 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद करने का दावा किया। इसके बाद पीएमएलए के तहत जांच शुरू हुई और मुख्यमंत्री को कई बार समन भेजे गए। ईडी का दावा है कि सोरेन सात बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने स्पष्ट किया कि सोरेन तीन बार पेश हुए थे और उसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह तथ्य इस पूरे मामले को एक अलग दृष्टिकोण देता है। क्या वास्तव में जांच में सहयोग नहीं किया गया था या फिर सहयोग के बावजूद कार्रवाई पहले से तय थी?

31 जनवरी 2024 को हुई गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर विस्फोट बना दिया था। गिरफ्तारी के बाद रांची की निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 174 के तहत समन जारी किया, जिसे चुनौती देते हुए सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि यह तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका निर्णय ट्रायल के दौरान होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस बात का संकेत है कि सर्वोच्च न्यायापालिका इस मामले को केवल तकनीकी नजरिए से नहीं, बल्कि व्यापक न्यायिक संतुलन और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में देख रही है।

मामले ने पकड़ा था राजनीतिक तूल

न्यायापालिका की ढाल और राजनीतिक संदेश

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में सोरेन को जिस तरह से जांच एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, उससे एक ऐसा माहौल बना जिसमें उनकी राजनीतिक छवि को चुनौती देने की कोशिश स्पष्ट दिख रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह रुख उस नैरेटिव को संतुलित करता है। अदालत का यह कहना कि ईडी को बड़े मामलों पर ध्यान देना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियों को अपनी प्राथमिकताओं और कार्रवाई की गंभीरता पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह फैसला सोरेन के लिए केवल कानूनी राहत नहीं, बल्कि नैतिक और राजनीतिक संबल भी है। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में, जहां सोरेन सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आदिवासी पहचान और अधिकारों के प्रतीक माने जाते हैं, वहां यह फैसला उनके समर्थकों के लिए न्यायापालिका की निष्पक्षता का प्रमाण बन सकता है।

एक व्यापक संकेत-संस्थाओं का संतुलन अभी कायम है

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था अभी भी संस्थागत संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। जांच एजेंसियों को कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन उस कार्रवाई की वैधता और औचित्य की अंतिम परीक्षा न्यायापालिका के सामने ही होती है। हेमंत सोरेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि न्यायापालिका न केवल सवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जांच और न्याय के बीच संतुलन बना रहे।

सुप्रीम कोर्ट की मुहर नवा केरल सर्वेक्षण पर लगी रोक हटी

केरल हाई कोर्ट ने केरल छात्र संघ की याचिका पर लगाई थी रोक

अब सर्वेक्षण फिर शुरू करने का रास्ता साफ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य के प्रस्तावित %नवा केरल सर्वेक्षण% को रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार को इस कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय ने केरल छात्र संघ (केएसयू) के नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं के बाद

कपिल सिबल ने लड़ा केस

उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट में राज्य की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने तर्क दिया कि सरकार के पास यह आकलन करने का अधिकार है कि कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों तक किस प्रकार की प्रभाव से पहुंच रही हैं और प्रशासनिक मूल्यांकन के लिए डाटा एकत्र करने का भी अधिकार है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारें उन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे सर्वेक्षण करने की हकदार हैं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोकने के आधार पर सवाल उठाया और पूछा कि कल्याणकारी कार्यक्रम इच्छित परिणाम दे रहे हैं या नहीं यह निर्धारित करने के लिए जानकारी एकत्र करने में क्या गलत था।

सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावों से पहले चलाया गया डाटा संग्रह अभियान सार्वजनिक धन से वित्त पोषित एक राजनीतिक

संयम बरतने की सलाह

इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी सर्वेक्षण की राजनीतिक आलोचना किसी राज्य को शासन संबंधी कार्य करने से रोकने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। अदालत ने प्रशासनिक मामलों में अनुचित न्यायिक हस्तक्षेप के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई स्पष्ट सवैधानिक उल्लंघन न हो, तब तक संयम बरतने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण को जारी रखने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लगभग 20 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

रूप से प्रेरित अभियान था। उच्च न्यायालय ने नवा केरल सर्वेक्षण को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था और इसके वित्तपोषण और क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम के लिए न तो उचित बजट आवंटन किया गया था और न ही वित्तीय स्वीकृति दी गई थी।

उमाशंकर छापा मामले में राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जताई आपत्ति

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उमाशंकर छापा मामले में बीजेपी में विद्रोह की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कई विधायकों ने दश शब्दों में नाराजगी जताई है। वहीं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह खुल कर उमाशंकर सिंह के साथ आ गये हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स उन्होंने लिखा है कि बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह के घर में मेरी बेटी ब्याही है। उनके घर में आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है।

देश प्रदेश के नेता और आयकर विभाग समेत सभी संस्थाओं को पता है कि उमाशंकर सिंह दो वर्ष से अधिक समय से ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में उमाशंकर सिंह के लिए धनार्जन नहीं, सांसें बचाने में ही सारा समय और धन व्यय हो रहा है। सभी व्यवसाय लगभग बंद हो गए हैं। आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं।



विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक घंटे के लिए भी नहीं जा सके। दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा, इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है। अगर उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की परिस्थितियों में दुर्लभतम अपराधों में भी माननीय न्यायालय दया के आधार पर याचिका स्वीकार कर दोषमुक्त कर देते हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं।

फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

टाइटल से समुदाय की छवि खराब नहीं होती,

27 फरवरी को तय समय पर रिलीज होगी फिल्म

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फिल्म के टाइटल और रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल किसी समुदाय की छवि खराब होने की आशंका के

आधार पर किसी फिल्म के टाइटल को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म के टाइटल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यादव समुदाय की छवि को ठेस पहुंचती हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला उन मामलों से अलग है जिनमें टाइटल स्पष्ट रूप से अपमानजनक या आपत्तिजनक पाए गए थे। अदालत की इस टिप्पणी के साथ ही फिल्म की रिलीज पर मंडरा रहा कानूनी खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। अब यह फिल्म तय कार्यक्रम के अनुसार 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जीपीएस से मॉनिटर होंगे बंगाल में तैनात जवान

पोलिंग के दिनों प्रभावी इस्तेमाल न होने की मिली थी शिकायत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से तैनात होने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को आवंटित वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे ताकि भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक लगातार निगरानी कर सकें कि तैनात सीपीएफ कर्मियों का पहले दिन से प्रभावी उपयोग हो रहा है या नहीं।

आयोग ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 मार्च को तैनात की जाने वाली सीपीएफ की 240 कंपनियों को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही तैनात किया जाएगा। उन्हें क्षेत्र पर कंट्रोल और राज्य की भौगोलिक स्थिति से परिचित होने के कार्य में लगाया जाएगा।

मूवमेंट ट्रैक करने के लिए जीपीएस

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, आयोग के निर्देशानुसार पहले दिन से प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन सीपीएफ कर्मियों को आवंटित वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे, ताकि आयोग की ओर से नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकें। पर्यवेक्षक सीपीएफ के इस्तेमाल पर दैनिक रिपोर्ट भी आयोग को भेज सकते हैं। सूत्र के अनुसार, यही व्यवस्था 10 मार्च को दूसरे चरण में तैनात होने वाली अतिरिक्त 240 कंपनियों पर भी लागू होगी।

प्रभावी इस्तेमाल पर सवाल

सीईओ ऑफिस के अंदरूनी सूत्र ने बताया, पश्चिम बंगाल में पिछले चुनावों में कई शिकायतें मिली थी कि बड़ी संख्या में सीपीएफ कर्मियों को तैनात करने के बावजूद पोलिंग के दिनों में भी उनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इयूटी के दौरान सीपीएफ कर्मियों के घूमने-फिरने की भी शिकायतें थीं। इसलिए ऐसी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस बार आयोग ने पहले दिन से ही सीपीएफ कर्मियों की मूवमेंट पर सख्ती से नजर रखने का फैसला किया है, ताकि शुरू से आखिर तक उनका प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।